

ISPRL to top up its caverns with cheap crude

MRPL pumps the crude to caverns

ANIL KUMAR SASTRY

MANGALURU

To make the best use of the low international crude prices, public sector oil companies, including Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. (MRPL) and Indian Strategic Petroleum Reserve (ISPRL), have been filling ISPRL's caverns at Mangaluru and Udupi with crude oil.

While ISPRL's Mangaluru cavern could store up to 1.5 million tonnes (MT) of crude, that of Udupi (at Padur) could store up to 2.5 MT. MRPL Managing Director M. Venkatesh said the first consignment of 2 million barrels by MRPL and the second of 1 million barrels by Indian Oil Corporation Ltd., had already been unloaded into the caverns.

Cargoes at lowest prices are lined up to reach the New Mangalore Port during

April and May to completely fill the caverns, the MRPL said in a release. The oil ministry has asked ISPRL to work closely with other oil companies to achieve the target, while MRPL plays its role in filling the caverns.

The series of crude oil cargoes of varying volumes from 1 million barrels to 2 million barrels, being sourced by MRPL, IOCL and Bharat Petroleum Corporation, would be unloaded at the Single Point Mooring (SPM) of MRPL, 17 km away from the shores in the Arabian Sea and within the jurisdiction of NMPT, before the onset of monsoon. The company is also filling its caverns at Visakhapatnam, the release quoted ISPRL as saying. Mr. Venkatesh said MRPL is sustaining the refinery operations at 50% capacity to meet the critical demand of LPG and fuel.

उज्ज्वला ने बढ़ाई घरेलू सिलेंडर की मांग

बताया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर 3 महीने तक फ्री देना है। इसके लिए खाते में राशि भी सरकार ने दी है। इससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला के हितग्राही शत प्रतिशत सिलेंडर भरवा रहे हैं। इससे मांग बढ़ी है। इसके पहले 50 प्रतिशत उपभोक्ता सिलेंडर रीफिलिंग करवाते थे। जिले में सवा 2 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला में कनेक्शन है।

GAIL infra projects: State-owned gas utility GAIL India Ltd on Saturday said it is ready to resume construction of various hydrocarbon infrastructure projects of national importance post lifting of the COVID-19 lockdown. "In order to kick start the crucial infrastructure projects to enable expansion of the gas based economy, GAIL along with its subsidiary and joint venture companies has chalked out catch-up plans for various locations and work fronts to ensure timely completion and avoid any slippages," the company said in a statement. PTI

GAIL eager to kick-start project execution once lockdown ends

NEW DELHI: State-owned gas utility GAIL India Ltd on Saturday said it is in readiness to resume construction of various hydrocarbon infrastructure projects of national importance post lifting of the COVID-19 lockdown.

"In order to kick start the crucial infrastructure projects to enable expansion of the gas based economy, GAIL along with its subsidiary and joint venture companies has chalked out catch-up plans for various locations and work fronts to ensure timely completion and avoid any slippages," the company said in a statement here.

Before the March 25 nationwide lockdown stopped all construction activities, GAIL was building multi-crore gas pipelines to connect fuel sources with consumption centres as well as setting up city distribution networks to sell CNG to automobiles and piped cooking gas to households.

"Graded measures in the short to medium term shall be rolled out starting from April 20 with the support of local admin-



istrative authorities across the states," the company said, adding it has facilitated arrangements for continued stay of the migrant labourers working at various sites/camps during the lockdown period for ensuring safety of all concerned.

Detailed SOPs / protocols have also been devised for ensuring hygiene and social distancing norms, promoting use of masks at the project sites and work stations in compliance with the instructions/guidelines issued by the Government of India, it said.

In parallel, GAIL has also maintained safe and uninterrupted supplies of LPG

to oil marketing companies and natural gas to the crucial downstream utilities such as fertilizer, power, refineries and city gas distribution, the statement said.

"Management of the company is in regular communication with the nodal ministry to seek guidance on issues requiring support for resuming full-fledged activities, post the phase of lockdown.

Key stake holders are also kept informed on the current developments as well as the proposed line of action under GAIL's complete readiness plan for returning to normalcy in the near term," it said. P11

GAIL lines up plans to restart infra projects after lockdown ends

SHINE JACOB

New Delhi, 18 April

State-run GAIL India has chalked out plans to kick-start various pipeline infrastructure projects, following the lifting of the Covid-19 lockdown.

Graded measures in the short to medium term will be rolled out starting April 20 with

the support of local administrative authorities across states. According to a GAIL official, projects of high pressure natural gas pipeline – including Urja Ganga Project connecting North and East India – will be taken up immediately.

“In order to kick-start the crucial infrastructure projects

and enable expansion of the gas-based economy, GAIL along with its subsidiary and joint venture companies has chalked out catch-up plans for various locations and workfronts to ensure timely completion and avoid any slippages,” said a GAIL statement. Management of the company is in regular communication with the nodal

ministry to seek guidance on issues requiring support for resuming full-fledged activities, after the lockdown phase. Key stakeholders are also kept informed on the current developments as well as the proposed line of action under GAIL’s complete readiness plan for returning to normalcy in the near term.

कूड 10 डॉलर तक होगा सस्ता! 97 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती भी नहीं रोक पाएगी गिरावट : एस.बी.आई. रिपोर्ट

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (एजेंसी): हाल ही में ओपेक और कूड के अन्य बड़े तेल उत्पादक देशों में कूड का प्रोडक्शन प्रतिदिन 97 लाख बैरल तक कम करने पर सहमति बनी है। कूड की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए ये देश प्रोडक्शन कम करने पर सहमत हुए। हालांकि इस समझौते के बाद भी कूड की इंटरनेशनल कीमतों

में गिरावट जारी है। कूड अभी 27 डॉलर प्रति बैरल के आस-पास ट्रेड कर रहा है। यह 18 साल का सबसे निचला स्तर है। हाल ही में जारी एस.बी.आई. इकोरैप रिपोर्ट में कूड के 10 डॉलर तक सस्ता होने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 97 लाख बैरल की कटौती कूड में गिरावट थामने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

अभी ब्रेंट कूड का भाव 27.82 डॉलर प्रति बैरल है, वहीं डब्ल्यू.टी.आई.

कूड 19.87 डॉलर प्रति बैरल के करीब है। यह फरवरी 2002 के बाद इसका सबसे निचला स्तर है। बता दें कि कूड में इस साल अब तक करीब 56.57 प्रतिशत गिरावट आ चुकी है। वहीं 1 साल में यह 58.87 प्रतिशत टूटा है। कूड में गिरावट इस साल के शुरू से ही बनी हुई है।

एस.बी.आई.

इकोरैप रिपोर्ट के अनुसार

97 लाख बैरल की कटौती कूड में गिरावट थामने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यह आने वाले दिनों में 10 डॉलर तक सस्ता हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल आयल स्टोरेज कैपेसिटी अभी 9 बिलियन बैरल है। इसमें से 7.2 बिलियन बैरल यूटिलाइज है, जबकि 1.8 बिलियन बैरल का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। 1.8 बिलियन बैरल 180 दिनों की सप्लाई के बराबर है।



कूड में क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट

इसके पीछे 3 प्रमुख वजह हैं। सबसे पहले ईरान और अमरीका के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से कूड में गिरावट आई। दूसरा कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन होने से कूड इंपोर्ट करने वाले देशों की ओर से मांग ठप्प पड़ गई। तीसरा ओपेक और रूस के बीच प्राइस वार छिड़ने से पिछले दिनों सऊदी अरब ने कूड प्रोडक्शन बढ़ा दिया और कीमतें कम कर दीं। सऊदी अरब की दिग्गज तेल कम्पनी अरामको ने मई महीने के लिए जिस तरह से तेल की कीमतें घोषित की हैं, उससे तो प्राइस वार कम होने की बजाय बढ़ती दिख रही है।



सरकार को नहीं मिल रहा राजस्व

पेट्रोल व डीजल से सरकार को सबसे अधिक राजस्व मिलता है लेकिन इनकी बिक्री घटने के कारण सरकार को राजस्व नहीं मिल रहा है। इसी तरह पेट्रोल पम्प संचालकों को प्रति लीटर में कमीशन मिलता है। इसमें वह कर्मचारी की वेतन व अन्य खर्चें वहन करते हैं लेकिन बिक्री नहीं होने से कमीशन कम मिल रहा है। ऐसे में उन्हें कर्मचारियों का वेतन तक निकलाना मुश्किल हो रहा है।



उज्ज्वला ने बढ़ाई घरेलू सिलेंडर की मांग

बताया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर 3 महीने तक फ्री देना है। इसके लिए खाते में राशि भी सरकार ने दी है। इससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला के हितग्राही शत प्रतिशत सिलेंडर भरवा रहे हैं। इससे मांग बढ़ी है। इसके पहले 50 प्रतिशत उपभोक्ता सिलेंडर रीफिलिंग करवाते थे। जिले में सवा 2 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला में कनेक्शन है।

डीजल-पेट्रोल की बिक्री 85 प्रतिशत की गिरावट, गैस सिलेंडर की बढ़ी खपत

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (एजेंसी): देश में लॉकडाऊन का सबसे अधिक डीजल-पेट्रोल की बिक्री में पड़ी है। स्थिति यह है कि जिले में डेढ़ लाख लीटर डीजल-पेट्रोल की बिक्री 15 से 20 हजार लीटर रोजाना में सिमट गई है। वहीं घरेलू गैस की मांग में 20 से 25 प्रति तक वृद्धि हुई है। इसके पीछे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री सिलेंडर की मिलने के कारण घरेलू गैस सिलेंडरों की मांग बढ़ी है।

बताया जा रहा है कि 22 मार्च के बाद कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश में लॉकडाऊन है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन बंद है। इसके साथ ही खाद्य वस्तुओं के मालवाहक वाहन चल रहे हैं। वहीं औद्योगिक इकाइयां व बड़े निर्माण काम भी बंद हैं। इसका सबसे अधिक असर डीजल एवं पेट्रोल की बिक्री पर असर पड़ा है। कम खपत होने के कारण पेट्रोल संचालकों की मुश्किल बढ़ी है। पेट्रोल पम्प संचालक बताते हैं कि पेट्रोल-डीजल की इससे पहले इतनी खपत काफी नहीं गिरी।

